

Publication	Date
Dainik Jagran (Print)	September 25, 2021

# खाद्य श्रृंखला को बचाएंगे एग्रो केमिकल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: फसलों की बोआई से लेकर रसोई के रास्ते खाने की थाली तक पहुंचने वाली लंबी श्रृंखला में खाद्यान्न का भारी नुकसान होता है। सिर्फ इसे रोकने में सफलता मिल जाए तो किसानों की आमदनी को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस लंबी खाद्य श्रृंखला को बगैर एग्रो केमिकल उपयोग के मजबूत बनाना संभव नहीं होगा। फसल सुरक्षा में रसायनों की बुनियादी जरूरतों पर चले दो दिवसीय मंथन में कृषि के सतत विकास के लिए रसायनों के विवेकपूर्ण व न्यायसंगत उपयोग का प्रमुखता से उल्लेख किया गया। मंथन के दौरान संसद की स्टैंडिंग कमेटी में लंबित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-2020 की खामियों को दूर करने पर विस्तार से चर्चा हुई।

केंद्रीय कृषि आयुक्त डा. एसके मल्होत्रा ने पेस्टिसाइड बोर्ड और रजिस्ट्रेशन कमेटी के सुधारों और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही। लेकिन देश में असंगठित कीटनाशक उद्योग को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त

## सुरक्षा

- कीटनाशक प्रबंधन विधेयक की खामियों को दूर करने का आग्रह
- कृषि के विकास के लिए रसायनों का विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी

की। देश में नकली और घटिया किस्म के कीटनाशकों की धड़ल्ले से होने वाली बिक्री पर लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने इसमें सुधार के लिए पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को आगे आने की सलाह दी। इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के सहायक उप महानिदेशक डा. एससी दुबे ने पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में स्वदेशी मालिकव्यूल्स (अणुओं) पर अनुसंधान किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों के खेतों पर होने वाली मुश्किलों का विस्तार से जिक्र करते हुए कीटनाशक उद्योग के लोगों से इसमें मदद करने का आग्रह किया।

फसलों पर कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह काम

जागरुकता के अभाव में ऐसा हो रहा है। इसके लिए उद्योगजगत को आगे आना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों को जगह-जगह खुली पेस्टिसाइड दुकान संचालकों को ट्रेनिंग देनी होगी। किसानों को कुछ भी दवा पकड़ाने की आदत से बाज आना होगा। इसमें इंडस्ट्री की जिम्मेदारी ज्यादा है।

जबकि उद्योग संगठन एग्रो केमिकल फेडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष एनके अग्रवाल ने कीटनाशक प्रबंधन बिल की खामियों को दुरुस्त करने का आग्रह किया। किसानों, डीलरों और वितरकों में जागरुकता बढ़ाने की जरूरत बताते हुए अग्रवाल ने कहा कि इसमें सरकारी तंत्र को साथ देना होगा।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में खामियों के मद्देनजर उसे संसदीय स्टैंडिंग कमेटी के विचारार्थ भेज दिया गया है। मंथन के दौरान विधेयक की विभिन्न कमियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पर सरकार की ओर से हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने भी हामी भरते हुए इसमें सुधार की उम्मीद जताई।